इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान सहित सभी राज्यों में केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्रक विशेष रोजगार कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे है, जिनमें चल रही केन्द्र प्रायोजित स्कीमें अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) तथा नेहरू रोजगार योजना (एस आर वाई) और केन्द्रीय क्षेत्रक स्वरोजगार स्कीम प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) प्रमुख हैं। सरकार ने हाल ही में, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) की एक "दो मिलियन जैब स्कीम" शुरू की है, जो उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में रोजगार, किसी भी अन्य राज्य की तरह राज्य में विकास की गति तथा पैटर्न पर निर्भर करता है जो मुख्यतः राज्य सरकार का दायित्व है तथा केन्द्र सरकार ऊपर बताए गए प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सहयोग देती है।

(ग) इन विशेष कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय निधियों के राज्य-वार आवंटन केवल वार्षिक योजनाओं में ही किए जाते हैं। वार्षिक योजना 1992–93, 1993–94 तथा 1994–95 में इन वर्षों के दौरान प्रचालित स्कीमों के संदर्भ में किए गए आवंटन अनुपत्र में दिए गए हैं। [देखिये परिशिष्ट 173, अनुपत्र सं० 111]।

Plan outlay for afforestation

5174. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what was the plan outlay for afforestation in 1994-95;

(b) what is the total expenditure for the year 1994-95 so far on this count;

(c) whether these plan executions are counter checked by competent authorities;

(d) whether it is a fact that under cover of afforestation the amount allocated is spent on other programmes; and

(e) remedial steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) Rs. 10100 lakhs.

(b) Rs. 9865.93 lakhs.

(c) In the schemes of the Board the expenditure is monitored by NAEB itself while in the schemes of Association of ST & Rural Poor in Degraded forests, the monitoring afforestation activity is envisaged through the regional offices of Ministry of Environment & Forests (MOEF).

(d) The funds allocated for afforestation under various schemes in the NAEB are not diverted to other programmes by the Board. No report regarding the diversion of funds allocated under the scheme of association of ST & Rural Poor in regeneration of degraded forests, has been received by the Ministry of Environment & Forests.

(e) Does not arise.

Development of Rural areas

5175. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any new programmes for the development of rural areas in the country particularly in the State of Punjab;